खाकी रामदेवी झूठ बनाम एलोपैथी लूट है असल मसला

विकास नारायण राय

स्वयं को स्वामी कहलाने वाले रामदेव के अनुसार एलोपैथी बकवास है और देश में होने वाली लाखों कोरोना मौतों के लिए जिम्मेदार भी! उसकी मानें तो कोरोना से लड़ाई एलोपैथी दवाओं और ऑक्सीजन से नहीं, उसकी पतंजलि नामक कंपनी के इम्युनिटी फॉर्मूले और प्राणायाम के दम पर लड़ी जानी चाहिए। इस क्रम में वह पेशेवर चिकित्सा समुदाय और महामारी कानून को रोज तिरस्कारपूर्ण चुनौती दे रहा है। अब एलोपैथी डॉक्टरों के संगठन ने प्रधान मंत्री से रामदेव के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की है।

यकीन जानिए, पुलिस को सबसे बुरा तब लगना चाहिये और लगता भी है जब कोई डंके की चोट पर कानून व्यवस्था की खिल्ली उड़ानी शुरू कर दे। लेकिन अगर सामने एक राजनीतिक रूप से बेहद समर्थ भगवा वस्त्रधारी हो तो? योग गुरु के रूप में मशहूर और आयुर्वेद को ढाल बनाकर धंधा जमाने वाले व्यापारी रामदेव ने अपने खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की आइएमए (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) की मांग पर ललकारा दिया है कि किसी का बाप भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। इस बीच कोरोना लड़ाई के दुष्कर दूसरे दौर में एलोपैथी पद्धति में जान का जोखिम उठाकर कार्यरत लाखों डॉक्टर व अन्य स्वास्थ्यकर्मी उसके दुष्प्रचार के निशाने पर चल रहे हैं।

रामदेव एक निरर्थक विवाद को जान-बूझकर खतरनाक रास्तों पर ले जा रहा है। वह इसे आयुर्वेद बनाम एलोपैथी का रूप देना चाहता है, जबकि सभी जानते हैं कि उसकी रणनीति कोरोना सन्दर्भ में रामबाण दवा की तरह प्रचारित किये गए अपने उत्पाद 'कोरोनिल' की निर्बाध बिक्री और व्यापक महामारी मुनाफे में हिस्सेदारी को लेकर है। जड़ी-बूटियों की बात करने वाले छद्म-विज्ञानी रामदेव की पेशेवर हैसियत कहीं से भी आयुर्वेद के वैध पैरोकार होने की नहीं है लेकिन वह इस पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का अरसे से स्वयंभू प्रवक्ता बना बैठा है। ठीक उसी तरह जैसे पतंजलि का नाम लेकर आसन/व्यायाम सिखाते-सिखाते वह योग गुरु बन गया था।

पतंजलि कंपनी की कोरोनिल का प्रचार एक तथाकथित रिसर्च बेस्ड कोरोना दवा के नाम पर किया जा रहा है। दावा है कि यह मरीजों पर ट्रायल से सिद्ध पायी गयी औषधि है। निरोधक, उपचारक और पोस्ट-केयर में खरी यानी तीन आयामी। यहाँ तक कि इस रिसर्च का पूरा डेटा भी है। लेकिन तथ्य यह है कि किसी भी मानक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से इस रिसर्च को कोरोना इलाज के लिए वैलिडेट नहीं कराया गया है। वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाईजेशन तो दूर रहा, किसी मान्य आयुर्वेदिक संस्थान से भी नहीं। यानी पतंजलि के तौर-तरीके विज्ञानी होने के दिखावे के बावजूद उसकी कोरोनिल एक छद्म-विज्ञान की उपज ही कही जायेगी।

'रामदेव का झूठ' सिक्के का एक पहलू भर है

भारत का संविधान लोगों में वैज्ञानिक मिजाज लाने के लिए काम करने का निर्देश देता है। खालिस कानूनी नजरिये से भी रामदेव और पतंजलि 2006 के महामारी अधिनियम के प्रावधानों के घोर उल्लंघन के ही नहीं, पुराने समय से चले आ रहे मैजिक रेमेडी एक्ट के अंतर्गत भी दोषी हैं। और परखा जाए तो रामदेव को अदालत की अवमानना का भी दोषी ठहराया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों ने भी एलोपैथी उपचार उपलब्ध न होने और ऑक्सीजन आपूर्ति में कमी के लिए केंद्र सहित तमाम राज्य सरकारों को आड़े हाथ लिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तो ऑक्सीजन के लिए तड़पती मौतों को जनसंहार तक कहा डाला। रामदेव का एलोपैथी पर अनर्गल हमला इस न्यायिक विवेक पर भी हमला है।

लेकिन 'रामदेव का झूठ' सिक्के का एक पहलू भर हुआ। इसे बल देने वाला दूसरा पहलू भी कम चिंताजनक नहीं। और वह है 'एलोपैथी की लूट' का। देश की पुलिस यहाँ भी प्रभावी कदम नहीं ले सकी है। कोरोना इलाज के हर चरण पर सरकार ने अधिकतम कीमत तय की हुयी है लेकिन निजी अस्पतालों में धड़ल्ले से लाखों का बिल वसूला जा रहा है। यही नहीं हर जरूरी दवा, उपकरण, बेड, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन, मरघट इत्यादि की जम कर कालाबाजारी हुयी है। ठीक है, महामारी में अमीर-गरीब सब शिकार बने हैं पर अपनी-अपनी पहुँच के हिसाब से इलाज की सुविधा का जुगाड़ करते हुए ही। इन आयामों पर रामदेव भी चुप है और आइएमए भी। दरअसल, आम आदमी के नजरिये से देखें तो बहस आयुर्वेद बनाम एलोपैथी न होकर 'रामदेवी झूठ' बनाम 'एलोपैथी लूट' होनी चाहिए।

रामदेव की सीनाजोरी की एक बड़ी वजह यह भी है कि वह एक वोट बैंक को अपील करता है और इसलिए सत्ता के दावेदारों को उसे छेड़ने से पहले कई बार सोचना होगा। काफी पहले से ही भाजपा, काँग्रेस समेत कई पार्टियों के मठाधीश उसे ढील ही नहीं बढ़ावा भी देते आ रहे हैं। उसके वोट बैंक के लिए कोरोनिल, बेशक छलावा सही, मंहगे अस्पतालों के आर्थिक बोझ की तुलना में कहीं अधिक आकर्षक है। उसका छद्म-विज्ञान समाज के एक बड़े अन्धविश्वासी तबके, जो वैक्सीन के बरक्स गौमूत्र पर अधिक विश्वास करना चाहता है, के लिए ग्राह्य हो जाता है। इस वोट बैंक की खातिर ही सत्ताधारी फिलहाल उसी तरह चुप है जैसे कभी बलात्कारी राम रहीम और आसा राम के कारनामों पर रहता था।

क्या रामदेव एक व्यापक षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार की कोरोना असफलता से ध्यान हटाने के लिए यह सब कर रहा है? इस बहस से स्वतंत्र भी मानना होगा कि कोरोना का वर्तमान काल कोई सामान्य समय नहीं है। दांव पर लाखों जान हैं। लिहाजा, देश में महामारी व्यवस्था की सफलता के लिए रामदेव के आयुर्वेदी झूठ से तुरंत निपटना भी उतना ही जरूरी हो गया है जितना एलोपैथी लूट से।

(पूर्व डायरेक्टर, नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद)

अब लक्षद्वीप हुआ मोदी सरकार की तानाशाही का शिकार

तेजिन्दर सिंह

क्या किसी सरकार को ये निर्धारित करने का अधिकार है कि क्षेत्र विशेष की जनता क्या खाए, क्या नही?

क्या सरकार की स्थानीय नीतियां स्थानीय लोगों के विचारों/सुझावों के अनुरूप नही होनी चाहिए? क्या सरकार को क्षेत्र विशेष के लिए नियम बनाने से पहले उसके लाभ हानि के पक्ष को लोगों से शेयर करते हुए एक खुली बहस नही करनी चाहिए?

लेकिन इन सभी बातों की उम्मीद आप इस केंद्र सरकार से नही कर सकते। इसके पूर्व के निर्णयों और लक्षद्वीप को लेकर उठाये गए वर्तमान के कदम सरकारी तानाशाही के गवाह हैं।

लक्षद्वीप को लेकर सारी समस्या तब से शुरू हुई जब 6 माह पूर्व प्रफुल्ल पटेल को लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर बना कर भेजा गया। प्रफुल्ल पूर्व में केंद्रीय सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसलिए स्वभाविक है कि उसी के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व इस पद पर केवल आई ए एस की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन ये सामान्य प्रथा से हटकर है। और स्वाभाविक है कि इसके पीछे कुछ निहितार्थ हैं।

1) सबसे पहले उन्होंने लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया। और विकास के नाम अथॉरिटी को टाउन प्लानिंग के बहाने ये अधिकार दिया कि वो किसी को भी उसकी जमीन से हटा या ट्रांसफर कर सकती है।

2) पूर्व में कोविड नियमों के तहत किसी को भी द्वीप में प्रवेश पर अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना पड़ता था। लेकिन प्रफुल्ल जी ने इसमे एक तरफा बदलाव कर इसमे 48 घंटे पहले का आर टी पी सी आर टेस्ट होने पर क्वांटिन से छूट दे दी गयी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इसी वजह से अब वहां 6000 से अधिक केस हैं।

3) लक्षद्वीप में अपराध की दर बेहद कम रहने पर भी जनवरी में सरकार ने PASA, प्रिवेंशन ऑफ एन्टी सोशल एक्टिविटीज एक्ट लागू कर दिया। जिसके तहत किसी को भी सार्वजनिक तौर पर जानकारी दिए बगैर एक साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। संक्षेप में इसे "गुंडा एक्ट" भी कहा जाता है।

4) डेवलपमेंट अथॉरिटी के ड्राफ्ट में कहा गया है कि अथॉरिटी के पास किसी को भी चल अचल संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और प्रबंधन की शक्ति है।

5) लक्षद्वीप एक 96 प्रतिशत मुस्लिम बहुल प्रदेश है लेकिन इसके बावजूद एनिमल प्रिवेंशन रेगुलेशन 2021 के तहत गौमांस उत्पाद के वध, परिवहन, खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

6) मुस्लिम बहुल प्रदेश होने के कारण यहां शराब शुरू से ही प्रतिबंधित थी। लेकिन अब उस प्रतिबंध को हटा लिया गया है। और बाकायदा इसके लिए लाइसेंस दिए जा रहे हैं।

प्रफुल्ल पटेल जी पर दादर नागर हवेली के एक सांसद मोहन डेलकर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगा है। मृतक डेलकर जी ने अपने आत्महत्या नोट में आरोप लगाया था कि उनसे 25 करोड़ मांगे गए और नहीं देने पर पीएएसए में फंसाने का डर दिखाया गया। आखिर केंद्र द्वारा एक आरोपित व्यक्ति को ऐसे पद पर बिठाने के क्या मायने हो सकते हैं। ये उनके द्वारा लाई गई नीतियों से समझा जा सकता है। जिन सब बातों की कभी स्थानीय लोगों ने मांग ही नही रखी, उनको लागू करने के पीछे छुपी उनकी मंशा को भी आसानी से समझा जा सकता है। दरअसल एक शांत और प्राकृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र को पर्यटन डेवलपमेंट के नाम पर कॉरपोरेट्स के हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है। ताकि संसाधनों की जम कर लूट की जा सके। साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक नियमों की अनदेखी करते हुए लोगों के आपसी सद्भाव और धार्मिक मान्यताओं पर भी चोट की जा रही है।

लक्षद्वीप का अधिकतर व्यापार केरल के कोचीन तट के रास्ते होता है। अब नए नियमों के तहत सरकार ने आदेश दिया है कि अब ये ब्यपार कर्नाटक के मंगलौर तट से होगा। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि केंद्र कर्नाटक में अपनी सरकार को लाभ पहुँचाना चाहता है।

केरल ने सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। वैसे भी लक्षद्वीप के लोग सामाजिक रूप से केरल से ज्यादा जुड़े हुए हैं। यहां के अधिकतर लोगों का दूसरा घर केरल में ही है। लक्षद्वीप के स्टूडेंट्स यूनियन ने लोगों को इसके विरुद्ध जागृत करना शुरू कर दिया है।

क्या ये ताज्जुब की बात नही है कि 96 प्रतिशत मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीफ बैन लाया गया और अल्कोहल बैन हटा लिया गया। ये दरअसल सरकार का वही नफरती एजेंडा है जिसके लिए सरकार जानी जाती है। और जो खेल ये हर जगह खेलती रहती है।

राष्ट्रीय उन्हें महज़ सिख नहीं कहिए, वे गोल्डन इंसान हैं

यूसुफ किरमानी

सिखों के गोल्ड दान की बहुत तारीफ़ हो रही है... वो लोग हमेशा तारीफ़ के क़ाबिल काम करते हैं।...इसमें रत्ती भर शक नहीं है। लेकिन मुझे गुस्सा उस आक्रमणकारी महमूद गजनवी और उन चंद मुगल हमलावरों पर आ रहा है जो हमारे देश के मंदिरों का सोना लूटकर ले गए। इन लोगों को क्या गाली दूँ? वो गोल्ड बचा रहता तो आज हमारे बहुसंख्यक भाई भी मंदिरों के गोल्ड से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अस्पताल बनवा रहे होते। लेकिन अभी भी बहुसंख्यकों का सामर्थ्य मरा नहीं है। उनकी दानवीरता के किस्से परोसे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुसंख्यकों में जोश की कमी है। जोश में आ जाएँ तो बहुसंख्यक सिखों के गोल्डन दान से भी बड़ा चमत्कार कर सकते हैं।

वे कहते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए जो कौम कई अरब रूपये चंदा दे सकती है। उसके लिए सैकड़ों यूनिवर्सिटी खड़ी कर देना मामूली बात है। अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लिए भी हिन्दू चंदा क्यों नहीं देंगे ? हिन्दू जाग उठा है। वह अब मंदिर से आगे जाकर सोच रहा है। मैं इस पर उन्हें मुबारक ही दे सकता हूं। उनके मुताबिक मुसलमान तो पंक्चर लगाने के स्तर से ऊपर नहीं उठ सका लेकिन बहुसंख्यक तो कहां से कहां पहुंच गए।

वो लोग इस शिकायत में कोई दम नहीं समझते हैं कि बहुसंख्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार आदि के बजाय मंदिर को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। उनके पैरोकार कहते हैं कि एक बार मंदिर बन जाये तो उसके बाद वे ज़रूर अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि की ज़रूरतों पर भी ध्यान देंगे। हालांकि देश में जिस हिसाब से मंदिर और अन्य पूजा स्थल कालांतर से बनते रहे हैं, अगर उसी समय से शिक्षा और स्वास्थ्य हर समुदाय की प्राथमिकता रहे होते तो आज हालात कुछ और होते।

बहरहाल, बात हम सिखों के गोल्डन दान पर बात कर रहे हैं। एक ऐसी कौम जो तमाम जुल्म सहने के बाद पूरी हिम्मत-ताकत के साथ फिर उठ खड़ी होती है। मुगलों ख़ासकर औरंगज़ेब ने सिख गुरुओं पर बहुत ही अत्याचार किए हैं। लेकिन गुरुद्वारे तो तब भी थे। आख़िर मुग़ल आक्रांताओं ने गुरुद्वारों से गोल्ड क्यों नहीं लूटा? हो सकता है लूटा भी हो। इतिहास में कहीं दर्ज भी होगा। लेकिन शायद मेरी नज़र से न गुजरा हो। कुछ मुगल शासकों के इतने अत्याचार के बाद भी सिख उठ खड़े हुए है। धन्य हैं गुरु नानक देव, जो सामाजिक भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता का महत्व अपने महत्वपूर्ण समय और भारतीय इतिहास के टर्निंग प्वाइंट के समय जानते थे। उस समय उन्होंने हर धर्म, जाति, ऊंच-नीच, अमीर-गरीब सभी के लिए लंगर की शुरुकात की थी जो आज एक मिसाल है। लंगर की परम्परा सभी मजहबों में है। लेकिन गुरुद्वारों में चलने वाले लंगरों से बाकी मजहबों के लंगर मुकाबला नहीं कर सकते। चौथे गुरु रामदास जी ने स्वर्ण मंदिर यानी हरमंदिर साहब की नींव रखी थी लेकिन उस समय दिसम्बर 1588 में नींव की पहली ईंट मियां मीर से रखवाई गई। यह गुरुनानक देव जी की इच्छा थी, जिसका पालन गुरु रामदास जी ने किया था। इस कहानी को संक्षेप में बताने का आशय यही है कि सिख धर्म शुरू से अपने मकसद को लेकर चला और आज भी वह मकसद ठीक उसी तरह से बरकरार है। उसमें किसी ने बदलाव की जुर्रत नहीं की।

सिखों पर 1984 में जो जुल्म हुए, वो आज भी भारत के माथे पर कलंक है। लेकिन आज भी हम उन जुल्म करने वालों को सिर्फ कांग्रेसी के नाम से जानते हैं लेकिन जिन लोगों ने सिखों का 1984 में कत्ल-ए-आम किया, किसी ने उनकी जाति और धर्म को नहीं बताया। किसी ने उन लोगों को कपड़ों से पहचानने की कोशिश नहीं की।

इस पर बहुसंख्यक समाज क्यों नहीं बात करता कि 1984 में सिखों पर जुल्म ढाने वालों की जाति और धर्म क्या था? उन्हें महज़ कुछ कांग्रेसी बताकर उनके धर्म और जाति के पाप को छिपाया नहीं जा सकता। 1984 के सिख विरोधी दंगे सिर्फ़ एक पार्टी की साज़िश नहीं थी। उसके पीछे एक और नाज़ी संगठन भी था। आखिर उस संगठन को चलाने वालों के धर्म और राजनीति पर बात क्यों नहीं की जा सकती? उसकी जाँच की माँग सिखों की तरफ़ से ही उठना चाहिए। लेकिन सिखों ने यह मांग कभी नहीं उठाई। उसके वकीलों ने उसे कांग्रेस के अलावा और कुछ सोचने ही नहीं दिखा।

सिखों से एक और चीज़ तमाम उन क़ौमों, उन वर्गों को सीखना चाहिए, जो अपने धर्म पर बहुत गौरव महसूस करते हैं और कराते हैं। सिखों की घनघोर सफलता का मूल मंत्र क्या है? खूब मेहनत करना, खूब पढ़ाई करना, कोई भी कारोबार करना चाहें छोटा हो या बड़ा हो, जीवन के प्रति आधुनिक नज़रिया रखना यानी दान में मिले गोल्ड को समाज के लिए अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाकर खर्च करना न कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुद्वारों पर ही खर्च करना।

इसके अलावा भी ढेरों खूबियाँ हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए आपके पास दिल, दिमाग़ और समय होना चाहिए। क्योंकि नाज़ी संगठनों के लोग और उनके अनुयायी इतना ही लिखे जाने पर बिदक जाएंगे। तो सिख भाइयों आपके जज़्बे को सलाम...आप लोग इसी तरह गुरू सेवा और सरबत दा भला करते रहें और तरक्की करते रहें...और बाक़ी कौम वालों ताली, थाली बजाओ...।

(वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक)